न्यायधीश रामेश्वर सिंह मलिक के समक्ष

दर्शनी देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 2012 का 13033

जनवरी 22.2013

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 53 - ग्राम पंचायत को हुई वित्तीय हानि - याचिकाकर्ता को बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए राशि जमा करने का निर्देश - जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा जांच की गई - वसूली नोटिस जारी - अपील और संशोधन याचिकाकर्ता खारिज कर दिया गया - सिविल रिट याचिका दायर की गई - अनुमति दी गई - आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त थे -हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 53 के उल्लंघन में पारित किया गया - कारण बताओ नोटिस दिए बिना वसूली नोटिस पारित नहीं किया जा सकता था।

यह निर्धारित किया गया कि पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारशील विचार करने के बाद, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेश सुटलर का है। पेटेंट अवैधता से, क्योंकि इसे 1994 के अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है।" रिट याचिका निम्नलिखित कारणों से अनुमति देने योग्य है।

(पैरा 8)

आगे कहा गया-, ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिए बिना, 15.7.2011 (अनुलग्नक पी -3) का आक्षेपित वसूली नोटिस जारी करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया, जैसा कि परिकल्पना के तहत किया गया है। 1994 के अधिनियम की धारा 5 3 (2)। याचिकाकर्ता का एक मूल्यवान अधिकार अवैध रूप से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा छीन लिया गया था, जबकि आक्षेपित वसूली नोटिस अनुलग्नक पी -3 पारित किया गया था।

(पैरा 11)

आगे आयोजित किया गया , यदि प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-2) की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया होता, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य था, तो याचिकाकर्ता अधिकारियों को समझाने की स्थिति में हो सकता था , प्रासंगिक आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए कि वह कथित तौर पर हुए नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं थी। 1 लोकेवर, चूँकि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था जिसके लिए वह कानूनन हकदार थी। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।

(पैरा 12)

आगे कहा गया कि मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित सभी तीन विवादित आदेश अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं और कानून की नजर में कायम नहीं रह सकते हैं। अधिकारी, 1994 के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अर्ध न्यायिक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं, 'वे पार्टियों के मूल्यवान अधिकारों का फैसला करते हैं। वास्तव में, यह निःसंकोच माना जाता है कि 1994 के अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित करें। ऑडी अल्टरम पार्टम के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस अधिनियम के तहत अधिकारी प्राकृतिक न्याय के इस बुनियादी नियम का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

(पैरा 14)

अरविंद सिंह, वकील, याचिकाकर्ता के लिए .

सुनील नेहरा, सीनियर डीएजी, हरियाणा राज्य के लिए।

न्यायधीश रामेश्वर सिंह मलिक

(1)'वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.2011 (अनुलग्नक पी-3) के खिलाफ निर्देशित है। नंबर 3, जिसके तहत याचिकाकर्ता को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए सीधे ग्राम पंचायत को हुई कथित वित्तीय हानि के कारण विवादित राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। परिणामी आदेश यानी अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश भी चुनौती के अधीन हैं।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य, तत्काल याचिका के निपटान के लिए आवश्यक हैं, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ एक शिकायत पर आधारित हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला-1 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की और अपनी रिपोर्ट संलग्नक पी-2 के माध्यम से प्रस्तुत की। 'आक्षेपित वसूली नोटिस दिनांक 15.7.2011 (अनुलग्नक पी-3), प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया। क्रमांक 3 में याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट अनुलग्नक पी-2 के आधार पर उसमें उल्लिखित राशि जमा करने के लिए कहा गया।

(3)आक्षेपित वसूली नोटिस से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने उपायुक्त के समक्ष अपनी अपील दायर की, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 24.8.2011 द्वारा (अनुलग्नक पी-4)। याचिकाकर्ता ने अपनी पुनरीक्षण याचिका (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से विद्वान वित्तीय आयुक्त से संपर्क किया। वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 10.1.2012 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) द्वारा याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया।

(4) प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत त्वरित याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया है, और इसे रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की है। विवादित आदेश. इस प्रकार, इस न्यायालय ने मामले को समझ लिया है।

(5) प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और उसके अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपना संयुक्त लिखित बयान दायर किया।

(6) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी जिला विकास अधिकारी नहीं था, जिसके कारण जांच कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि केवल तर्क के लिए, भले ही जांच रिपोर्ट अनुलग्नक पी-2 को उचित प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया गया माना जाता है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 3 ने आक्षेपित वसूली नोटिस अनुलग्नक पी- जारी करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया। 3. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 भी कानून की गंभीर त्रुटि में पड़ गए, जबकि इस तथ्य की सराहना नहीं की गई कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी किया गया नोटिस क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त था, इसलिए तीनों विवादित आदेश उत्तरदायी थे। रद्द करना। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 1994 का अधिनियम') की धारा 53 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि लागू आदेशों के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर हानि हुई है, जो धारा के प्रावधानों का उल्लंघन है। 1994 के अधिनियम के 53 (2) कानून में टिकाऊ नहीं थे। अत: वह इस याचिका को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करता है।

(7) इसके विपरीत, राज्य के लिए संयुक्त वकील का कहना है कि चूंकि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश मामले के सही तथ्यों पर आधारित थे, इसलिए प्राधिकारियों ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, अर्थात यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला गया कि रिट याचिका बिना किसी योग्यता के थी और खारिज होने योग्य थी।

(8) मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और विचारशील विचार करने के बाद, पक्षों के विद्वान वकील को काफी देर तक सुना गया। दोनों पक्षों की ओर से बीसीएल पर उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त हैं, क्योंकि इसे 1994 के अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है। रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए निम्नलिखित कारणों से।

(9) चूंकि वर्तमान मामला 1994 के अधिनियम की धारा 53 के आसपास घूमता है, इसलिए धारा 53 को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है: -

"सरपंच या पंच का दायित्व। -

(1) प्रत्येक सरपंच या ग्राम पंच का पंच ग्राम निधि या उस ग्राम पंचायत से संबंधित संपत्ति की हानि, बर्बादी या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, बर्बादी या गलत उपयोग होता है जैसा भी मामला हो, सरपंच, उप-सरपंच या पंच के रूप में काम करते समय उसकी उपेक्षा या कदाचार का परिणाम हो सकता है।

(2) संबंधित झुंड विकास और पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा, नुकसान के लिए, ग्राम निधि या उस ग्राम पंचायत से संबंधित संपत्ति की बर्बादी या गलत उपयोग और सरपंच या पंच को, जैसा भी मामला हो, समझाने का पर्याप्त अवसर देने के बाद, ऐसे नुकसान के कारण उससे देय राशि का लिखित आदेश द्वारा आकलन करना, ऐसी ग्राम निधि या संपत्ति की बर्बादी या दुरुपयोग और इसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(3) निदेशक को इसे अलग रखना होगा और निदेशक ऐसे आदेश को लागत, अदालत में भुगतान या अन्यथा जैसी शर्तों पर निलंबित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, लेकिन ऐसे आवेदन के परिणाम के अधीन, यदि कोई हो, आदेश देय राशि का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के बावजूद, सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इस संबंध में प्राप्त आवेदन से किसी भी रिकॉर्ड की मांग कर सकती है। ऐसी कार्यवाही जिसमें निदेशक ने ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उपधारा (3) के तहत एक आदेश पारित किया है और वह उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, बशर्ते कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

(5) इस उपधारा के तहत किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करें। हानि, हानि, बर्बादी या दुरुपयोग की घटना से छह साल की समाप्ति के बाद या उसके पंच के सरपंच के पद से हटने के दो साल की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो।

(6)राशि जैसा भी मामला हो, सरपंच या पंच से बकाया के रूप में मूल्यांकन किया गया, उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों से उन्हें विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक वसूल किया जा सकता है। "

(10)इस बात का कोई कारण सामने नहीं आया है कि विद्वान उपायुक्त-प्रतिवादी नंबर 2 ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी के बजाय जिला विकास और पंचायत अधिकारी को जांच क्यों सौंपी, जैसा कि अधिनियम की धारा 53 के तहत परिकल्पित है। भले ही मामले के इस पहलू को इस कारण से नजरअंदाज कर दिया जाए कि इस कारण याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है, चाहे प्रतिवादी संख्या 2 या जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंबाला-1, ने प्रतिवादी संख्या से कभी नहीं पूछा। 3 सीधे वसूली नोटिस जारी करें। दूसरी ओर, उन्होंने केवल प्रतिवादी संख्या 3 को 1994 के अधिनियम की धारा 51 और 53 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। ऐसा लगता है कि प्रतिवादी संख्या 3 काफी समय तक मामले पर बैठी रही और फिर अचानक सीधे दिनांक 15.7.2011 को वसूली नोटिस जारी कर दिया (अनुलग्नक पी-3)। विवादित पुनर्प्राप्ति नोटिस को देखने से पता चलता है कि यह 1994 के अधिनियम की धारा 53 (3) के उल्लंघन में जारी किया गया था, जिसे ऊपर प्रस्तुत किया गया है।

(11) जे लविंग ने कहा, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिए बिना, 15.7.2011 (अनुलग्नक पी -3) के खिलाफ वसूली नोटिस जारी करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया। जैसा कि 1994 के अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत परिकल्पित किया गया है। याचिकाकर्ता का एक मूल्यवान अधिकार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अवैध रूप से छीन लिया गया था, जबकि आक्षेपित वसूली नोटिस अनुलग्नक पी -3 पारित किया गया था।

(12) प्रतिवादी संख्या थी .3 ने याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-2) की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य था, याचिकाकर्ता अधिकारियों पर भरोसा करते हुए उन्हें समझाने की स्थिति में हो सकता था। प्रासंगिक आधिकारिक रिकॉर्ड है कि कथित तौर पर हुए नुकसान के लिए वह ज़िम्मेदार नहीं थी। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता को खुद का बचाव करने का अवसर देने से इनकार कर दिया गया था जिसके लिए वह कानून में हकदार थी, इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।

(13)'प्रतिवादी द्वारा पारित किया गया आदेश क्रमांक 3, जो अधिकार क्षेत्र के बिना एक आदेश था, पर अपीलीय के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से विचार और सराहना नहीं की गई थी। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष दायर अपने पुनरीक्षण के पैरा 6 में, याचिकाकर्ता ने एक विशिष्ट रुख अपनाया कि आदेश दिनांक 15.7.2011 (अनुलग्नक पी -3), 1994 के

अधिनियम के प्रावधानों से परे था और याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, उसे अपना बचाव करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 अपने आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 10.1.2012 (अनुलग्नक पी-6) को पारित करते समय मामले के इस पहलू की सराहना करने में भी विफल रहा।

(14)मामले के इस दृष्टिकोण में, तीनों ने आक्षेप लगाया प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं और कानून की नजर में टिक नहीं सकते। 'अधिकारी, 1994 के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अर्ध न्यायिक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। वे पार्टियों के मूल्यवान अधिकारों का फैसला करते हैं, 'इस प्रकार, यह निस्संदेह माना जाता है कि 1994 के अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है ,नफे सिंह बनाम हरियाणा राज्य~(जितेंद्र) चौहान, जे.) सावधानीपूर्वक। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित करें। ऑडी अल्टरम पार्टेम के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है और अधिनियम के तहत अधिकारी प्राकृतिक न्याय के इस बुनियादी नियम का विषयगत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

(15)कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(16) ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, यह माना जाता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15.7.2011 (अनुलग्नक पी-3), 24.8.2011 (अनुलग्नक पी-4) और 10.1.2012 (अनुबंध पी-6) कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। ये सभी तीन विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्द्वारा रद्द किया जाता है

(17) उपरोक्त के मद्देनजर, मामला खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला-एल-प्रतिवादी संख्या को भेजा जाता है। 3, कानून और यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए।

(18)परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

जे.एस.एम.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा